खण्ड–8, अंक–1, वर्ष–2020
D.O.I.: 10.22445/avsp.v8i1.32

वैज्ञानिक आलेख

आधुनिक राज्यों के विकास का क्रमः अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों में एक वैचारिक अध्ययन

नेविल डी. कुन्हा

अंतर्राष्ट्रीय सम्बंध एवं कूटनीति विभाग, टिश्क इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी–एरबिल, इराक

प्राप्ति तिथि–30.09.2020, स्वीकृति तिथि–27.11.2020

सार– 21वीं सदी की अस्थिर और तेजी से बदलती दुनिया में यह समझना महत्वपूर्ण है कि वैश्विक स्तर पर चीजें वास्तव में कैसे काम करती हैं। इसलिए इस लेख का उद्देश्य इस तेजी से बदलती दुनिया की व्यावहारिक वास्तविकता पर जोर देना है और उस व्यावहारिक वास्तविकता को अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों के अकादमिक अध्ययन के साथ जोड़ना है। अंतर्राष्ट्रीय सम्बंध (इंटरनेशनल रिलेशन) के अध्ययन में कई महत्वपूर्ण प्रश्न संप्रभु राज्य के सिद्धांत और व्यवहार से जुड़े हुए हैं जो वैश्विक राजनीति का केंद्रीय ऐतिहासिक संस्थान है। यह लेख आई.आर. के मूल ऐतिहासिक विषय आधुनिक संप्रभु राज्यों और राज्यों प्रणाली के अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों पर ध्यान केंद्रित करके उस सम्बंध को बनाता है। राज्य प्रणाली के ऐतिहासिक विकास को रेखांकित करने के बाद, आगे तीन मुख्य कारक जिन्हें प्रत्येक राज्य को अपने अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए ध्यान में रखना है और निरंतर प्रासंगिकता को संक्षेप में बताया जाएगा और फिर एक निष्कर्ष निकाला जाएगा। यह वैचारिक अध्ययन हमें राज्यों और राज्यों की प्रणाली के ऐतिहासिक और सामाजिक आधार को आधुनिक राजनीतिक जीवन की मूल विशेषता के रूप में समझने में सक्षम बनाता है। यह अध्ययन निश्चितता के साथ यह जानने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है कि क्या राज्य प्रणाली अब अप्रचलित हो रही है या क्या राज्य वैश्वीकरण के युग में नई चुनौतियों का सामना करने के तरीके खोजेगा। यह लेख आई.आर. छात्रों के लिए एक प्रारम्भिक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता है और गहराई से अध्ययन और अनुसंधान दोनों के लिए प्रशिक्षकों के निर्देशों का उपयोग कर सकता है।

बीज शब्द– स्टेट्स, स्टेट्स सिस्टम, जियोपॉलिटिक्स, नेशनल इंटरेस्ट, पॉवर ऑफ बैलेंस

The Evolution of Modern Sovereign States: A Conceptual Study in International Relations

Neville D'Cunha

Department of International Relations and Diplomacy, Tishk International University-Erbil, Iraq

Abstract- In the 21st century's volatile and fast changing world, it is important to understand how things really work on the global stage. Hence, the aim of this article is to emphasize the practical reality of this fast changing world and to connect that practical reality with the academic study of international relations. Many important questions in the study of International Relations (IR) are connected with the theory and practice of sovereign statehood which is the central historical institution of global politics. This article makes that connection by focusing on the core historical subject matter of IR: modern sovereign states and the international relations of the states system. After outlining the historical evolution of the state system, further, three main factors that every state has to take into consideration to foster their existence and continuing relevance will be briefly stated and then a conclusion will be drawn. This conceptual study can enable us to understand the historical and social basis of states and the states system as the basic feature of modern political life.This study can make a significant contribution in knowing with certainty whether the states system is now becoming obsolete,

Corresponding Author: neville.dcunha@tiu.edu.iq

or whether states will find ways of adapting to new challenges in the era of globalization. This article can serve as a beginner's guide to IR students and instructors with implications for both in-depth study and research.

Key words- States, States system, geopolitics, National Interest, Balance of Power (BOP)

1. अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों का अध्ययन क्यों करें?

जिस दुनिया में हम रहते हैं, वह राज्यों में विभाजित है। राज्य को परिभाषित करने में हेवुड[4] बताते हैंः "राज्य शब्द का प्रयोग चीजों की एक भयावह सीमा को संदर्भित करने के लिए किया गया है" संस्थानों का एक संग्रह, एक प्रादेशिक इकाई और एक दार्शनिक विचार, जबरदस्ती या उत्पीड़न का एक साधन, और जल्द ही। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वास्तव में दुनिया की पूरी आबादी उन अलग–अलग क्षेत्रीय समुदायों की सीमाओं के भीतर रहती है जिन्हें हम राज्य कहते हैं वर्तमान में सात अरब से अधिक लोग एक राज्य या किसी अन्य के नागरिक या विषय हैं। राज्य एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, कम से कम कानूनी रूप से उनकी संप्रभुता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे एक दूसरे से अलग या अछूते हैं। इसके विपरीत, वे एक–दूसरे से सटे होते हैं और एक–दूसरे को प्रभावित करते हैं और इसलिए सह–अस्तित्व और एक–दूसरे से निपटने के तरीके खोजने चाहिए। दूसरे शब्दों में, वे एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमा का निर्माण करते हैं– आई.आर. का मुख्य विषय।[5,6,9] इस बातचीत का स्वरूप निश्चित रूप से आधुनिक, वैश्वीकरण के युग में बदल गया है। जब राज्य आपस में बातचीत करते हैं, तो ये इंटरैक्शन इन राज्यों की घरेलू आबादी को प्रभावित करते हैं। जब दुनिया के सभी राज्य आपस में बातचीत करते हैं, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय राज्यों की व्यवस्था बनाता है। अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिमा में राज्यों के बीच होने वाली बातचीत घरेलू आबादी के लिए ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक–आर्थिक परिणाम तैयार करती है। आई.आर. इन अंतरराष्ट्रीय सम्बंधों की प्रकृति और परिणामों का अध्ययन है।

आई.आर. का अध्ययन करने का मुख्य कारण यह तथ्य है कि दुनिया को अलग–अलग राजनीतिक समुदायों, या स्वतंत्र राज्यों में विभाजित किया गया है, जो लोगों के जीने के तरीके को गहराई से प्रभावित करते हैं। राज्य के लिए आई.आर. दृष्टिकोण इसे मुख्य रूप से विश्व मंच पर एक अभिनेता के रूप में देखता है वास्तव में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मूल इकाई के रूप में।[4] जैक्सन एंड सोरेनसन[5] के अनुसारः "एक स्वतंत्र राज्य को एक स्थायी आबादी के साथ एक स्थायी और सीमावर्ती क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, सर्वोच्च सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत, जो कि सभी विदेशी सरकारों से अलग हैः एक संप्रभु राज्य। वर्तमान समय में, दुनिया भर में 195 राज्य बिखरे हुए हैं, जिनमें से 193 राज्यों को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है। हालाँकि, अब हमारे मन में यह सवाल उठ रहा है कि राज्य की अवधारणा मुख्य रूप से क्या करती है? यह कैसे विकसित हुआ? अगला खंड राज्य के विकास की एक संक्षिप्त झलक प्रदान करने का प्रयास करता है। यह हमें प्राचीन काल से वैश्वीकरण की आयु तक अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक संदर्भ में राज्य के अध्ययन की गहन बारीकियों को समझने में मदद करेगा। इसके अलावा, हम उन तीन कारकों का पता लगाएंगे जिन्हें हर राज्य को अपने अस्तित्व के लिए किसी भी चुनौती को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। पहले, आइए हम आधुनिक राज्यों के क्रमिक ऐतिहासिक विकास की ओर अपना ध्यान आकर्षित करें।

2. आधुनिक राज्यों का विकास कैसे हुआ?

2.1 प्रारंभिक राज्य प्रणाली

प्रारम्भ में इंसान ग्रामीण थे। उनमें से ज्यादातर खानाबदोश जीवन जी रहे थे। समय के साथ, जैसे कि इन खानाबदोशों ने कृषि की तकनीक विकसित की और जानवरों के वर्चस्व को सीखा, उन्हें एक सुलझे हुए जीवन के पक्ष में खानाबदोश जीवन के साथ दूर करने के लिए मजबूर किया गया। जैसे–जैसे वे एक क्षेत्र में बसते गए, जमीन के उस हिस्से में आबादी बढ़ने लगी। समय के साथ यह धीरे–धीरे एक सूक्ष्म जगत समाज में बदल गया। चूंकि यह मिनी–सोसाइटी एक स्थान पर स्थापित हो गई थी, इसलिए इसने अन्य क्षेत्रों में भी काम किया।[6,9] प्रारंभ में, इन सभी समाजों को नदियों या अन्य पीने योग्य जल–स्रोतों के पास क्लस्टर किया गया। यह मुख्य कारण है कि सभी प्राचीन सभ्यताओं के बहुमत प्रमुख बारहमासी नदियों के पास पाए जाते हैं। जैसा कि अराजक आदिवासी सामाजिक समूह समय की अवधि में बढ़े, सदस्यों के लिए एक आचार संहिता स्थापित करने के लिए एक दबाव की आवश्यकता महसूस की गई ताकि आदेश का एक रूप लगाया जा सके। सामाजिक अंतर्क्रियाओं के नियम स्थापित हो जाने के बाद, इन नियमों को लागू करने के लिए एक प्राधिकरण बनाने की आवश्यकता हुई। प्रारम्भ में, इसने अधिकांश बड़े लोगों पर अधिकार का उल्लेख करने के रूप में इसकी अभिव्यक्ति को देखा,

लेकिन, यह धीरे–धीरे समूह के सबसे मजबूत व्यक्ति में बदल गया। समय–समय पर, व्यक्तियों के समूह की रक्षा के लिए एक आवश्यकता महसूस की गई थी, अब दूसरे समूहों के सदस्यों द्वारा हमलों से निपटारे के रूप में। इसने न केवल लोगों की भौतिक सुरक्षा में, बल्कि भूमि पर भी कब्जा कर लिया। इस प्रकार, संरक्षण एक मजबूत प्रमुख के नेतृत्व में राजनीतिक संरचनाओं के सबसे अल्पविकसित कारण के रूप में उभरा।

एक स्थान के इन समूहों ने कुछ दूरी पर स्थित अन्य समूहों के साथ भी बातचीत की। इस अंतःक्रिया की प्रकृति अक्सर भिन्न होती है। समय के साथ बातचीत दूसरे क्षेत्र को वशीभूत करने के लिए थी और किसी के अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए या कई बार, आपसी सह–अस्तित्व को प्राप्त करना था। क्षेत्र के रक्षक और अब तक इसकी आबादी को राजा कहा जाता था और राजा को इन प्राचीन काल के दौरान दिव्य शक्तियों का अधिकारी माना जाता था।

प्राचीन काल में, संप्रभुता की अवधारणा का पूर्ण अभाव था। फिर भी, राज्य संप्रभुता के अभाव में हमने प्राचीन साम्राज्यों को फलते–फूलते देखा है। बहुत सफल प्राचीन साम्राज्यों में से एक ग्रीक शहर–राज्यों की व्यवस्था थी। इसमें एक सामान्य भाषा और धर्म था। यूनानी बाद में रोमन के विषय बन गए। रोमन काल के दौरान, प्राधिकरण की अवधारणा में बहुत बदलाव आया। सम्राट के साथ–साथ पोपसी (पोप) का एक नया अधिकार उभरा।

2.2 मध्यकालीन राज्य प्रणाली

मध्यकालीन समाज सामंतवाद के रूप में स्थापित हो गया। जैक्सन एंड सोरेनसन[5] नोटः "मध्यकाल में, राजनीतिक अधिकार अराजक और बिखरे हुए थे। अधिकांश लोग विभिन्न अधिकारियों की एक बड़ी संख्या पर निर्भर थे– उनमें से कुछ राजनीतिक, कुछ धार्मिक– विविध जिम्मेदारियों और शक्ति के साथ, स्थानीय शासक और जमींदार राजा के लिए एक दूर की राजधानी में, पुजारी से दूर पोप तक। रोम को देखो इसलिए, मध्ययुगीन गणतंत्र क्रिस्टियाना, सैद्धांतिक रूप से ईश्वर की संप्रभुता के तहत एक जैविक समुदाय था, जिसे पोपियों ने मध्यस्थ बनाया था। मध्ययुगीन यूरोप की राजनीतिक प्रणाली इस प्रकार स्थानीय और सार्वभौमिक का एक उत्सुक संयोजन थी। फिर भी, चौदहवीं शताब्दी से इस प्रणाली को बहुत सरल बना दिया गया क्योंकि राज्य स्थानीय और सार्वभौमिक के बीच एक मध्यवर्ती स्तर पर स्थित एक राजनीतिक इकाई के रूप में उभरा। नए राज्यों ने एक साथ खुद को सार्वभौमिक स्तर पर चबूतरे और सम्राटों के विरोध में स्थापित किया, और स्थानीय स्तर पर सामंतों, किसानों और अन्य शासकों को एकत्र किया। इस तरह से यह राज्य अपने आप को स्वतंत्र और स्वशासित बनाने के लिए आया।[6] सामंती मध्ययुगीन व्यवस्था प्रभावी रूप से आयु के आगमन के साथ टूट गई थी, इसके बाद पुनर्जागरण और सुधार हुआ। आखिरकार वेस्टफेलिया की संधि में इसका समापन हुआ। 1648 में जिसने संप्रभुता के विचार के आधार पर पहली बार आधुनिक राज्यों का निर्माण किया। इस संधि का सार यह था कि प्रत्येक राष्ट्र–राज्य की अपने क्षेत्र और घरेलू मामलों पर संप्रभुता है, सभी बाहरी शक्तियों को शामिल करने के लिए दूसरे देश के घरेलू मामलों में गैर–हस्तक्षेप का सिद्धांत, और प्रत्येक राज्य, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में कितना ही बड़ा या छोटा क्यों न हो। इसलिए, यह इतिहास में पहली बार था कि विकसित राज्यों–प्रणाली ने अंतरराष्ट्रीय कानून और शक्ति के क्षेत्रीय संतुलन (डी.कुन्हा[2]) को विकसित करके एक स्थिर अंतरराष्ट्रीय अराजकता बनाने की मांग की। यूरोप में राज्यों–प्रणाली के समेकन के बाद, इसके बाद भौगोलिक खोजों, प्रबुद्धता, कारण की उम्र और साम्राज्यवाद का पालन किया गया।

तालिका–1

पूर्व–आधुनिक राज्यों की प्रणाली का कालक्रम

शहर–राज्य और साम्राज्य	
500 बी.सी.ई.–100 बी.सी.ई.	ग्रीक सिटी–स्टेट सिस्टेम्स (हेल्लास)
200 बी.सी.ई.–500 बी.सी.ई.	रोमन एम्पायर
306 बी.सी.ई.–1453 बी.सी.ई.	आर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी : बाइजेन्टाइन एम्पायर, कॉन्स्टेन्टिनोपल
500 बी.सी.ई.–1500 बी.सी.ई.	कैथोलिक क्रिस्टेन्डोम : द पोप इन रोम
1299 बी.सी.ई.–1923 बी.सी.ई.	ओट्टोमान (टर्किश) एम्पायर, इस्तान्बुल (कॉन्स्टेन्टिनोपल)
अदर हिस्टॉरिकल एम्पायर्स	पर्शिया, इंडिया (मुगल), चीन

स्रोतः जैक्सन एंड सोरेनसन[5]

2.3 द मॉडर्न स्टेट्स सिस्टम

आधुनिक राज्य को समझने के विभिन्न तरीकों के बावजूद, यह कब और कहाँ उभरा, इसके बारे में सामान्य सहमति है। आधुनिक राज्य एक ऐतिहासिक संस्था हैरू यह सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी के यूरोप में एक केंद्रीकृत शासन की प्रणाली के रूप में उभरा, जो चर्च (और विशेष रूप से) सहित सभी अन्य संस्थानों और समूहों को अधीन करने में सफल रहा, जिससे प्रतिस्पर्धा और अतिव्यापीता समाप्त हो गई। मध्ययुगीन यूरोप (हेवुड)[4] की विशेषता रखने वाली प्राधिकरण प्रणालियाँ। वेस्टफेलिया की संधि ने मध्यकालीन राजनीतिक सेट–अप से लेकर आधुनिक जीवन शैली तक के राजनीतिक बदलावों के बारे में संधि के प्रावधानों को एकतरफा और स्वतंत्र के एकल ढांचे के तहत समेकित किया। सामाजिक संगठन संप्रभु राज्य।

पश्चिम में पहली प्रलयकारी घटना अमेरिकी क्रांति थी। प्रज्वलन और संघर्ष को बनाए रखने में प्रबुद्ध विद्वानों का प्रभावी योगदान था। थॉमस जेफरसन, जॉन लोके, मिल्टन और थॉमस पेन के निरंतर बौद्धिक योगदान इस बात का प्रमाण हैं। 1776 में, अमेरिका आखिरकार एक गणतंत्र बन गया। इसने अपनी राह में स्थिरता[9] में गृहयुद्धों के रूप में अपनी परेशानियों को देखा। लेकिन अमेरिकी क्रांति के दो महत्वपूर्ण परिणाम थे। पहला यह था कि इसने फ्रांस में क्रांति के लिए बीज बोए थे और दूसरा, लोकतंत्र के आदर्श को फ्रांसीसी द्वारा प्रेरणा के रूप में देखा गया था। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के लिए यह मार्ग प्रशस्त हुआ जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों पर आधारित था। फ्रांसीसी क्रांति द्वारा फैलाए गए विचारों ने 1945 तक लगभग यूरोपीय लोगों के बीच गहराई से प्रतिध्वनित किया। औद्योगिक क्रांति और उपनिवेशीकरण के साथ इस अवधि के दौरान उभरे हुए व्यापारीवाद ने दुनिया को अंततः विश्व युद्ध के लिए प्रेरित किया। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पुनर्जागरण, ज्ञानोदय और औद्योगिक क्रांति ने यूरोप को पुनर्प्राप्ति और उत्थान के रास्ते पर डाल दिया था। यूरोप को विश्व शक्ति के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक बनने का समय नहीं था। औद्योगिक क्रांति ने संसाधनों और नए बाजारों की खोज का नेतृत्व करने के लिए कई यूरोपीय देशों का नेतृत्व किया था। इस की अभिव्यक्तियों में से एक साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद था। अफ्रीका और एशिया एक साम्राज्यवादी यूरोप[3] के लिए नए युद्ध के मैदान थे। जैसे–जैसे औद्योगिक क्रांति यूरोप में आगे बढ़ी, इसने मजबूत, अधिक शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं को घर वापस बनाया। यदि 1648 में वेस्टफेलिया की संधि ने राष्ट्र–राज्यों के रूप में मजबूत राजनीतिक संस्थाओं का उदय किया, तो यह औद्योगिक क्रांति है जिसने यूरोप में मजबूत अर्थव्यवस्थाएं बनाईं। 1900 तक कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, हाप्सबर्ग साम्राज्य, जापान, इटली, अमेरिका और जर्मनी थीं।

1900 तक, यूरोप आर्थिक रूप से खुद को मजबूत करने में सक्षम था, लेकिन एक बहुत ही अस्थिर स्थिति में भी था क्योंकि आर्थिक सफलता ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की एक दौड़ को प्रज्वलित किया जिसने सत्ता के यूरोपीय संतुलन को खतरा और सत्ता के संतुलन को बनाए रखने के लिए तीव्र अंतर–राज्य प्रतिद्वंद्विता पैदा की। गठबंधनों का गठन किया गया था, जो फिर से एक युद्ध के प्रकोप का कारण बना। ध्यान देने योग्य बात यह है कि, वेस्टफेलिया की शांति और वेस्टफेलियन राज्यों के उभरने के बाद से, कमांड या राजाओं के राजा न केवल अपनी शक्ति में निरपेक्ष हो गए, बल्कि अपने राज्यों[5] पर पापल अधिकार को भी त्याग दिया। यह वास्तव में राज्य के शासन में यह परिवर्तन है जिसने आधुनिक राज्य–व्यवस्था को जन्म दिया है। इन राजाओं के शासन में राज्य फलने–फूलने लगे। नई–मिली स्वतंत्रता ने साम्राज्यवाद जैसी प्रथाओं का विस्तार करने और लिप्त होने का आग्रह किया। साम्राज्यवादी दुनिया ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपना कठिन सबक सीखा, लेकिन यह समझौता वर्साय की प्रथम विश्व युद्ध के कुख्यात संधि के माध्यम से पहुंचा, जिसने अगले विश्व युद्ध– द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बीज बोया। 1919 की वार्साय की संधि[9] के अंत में एक ऐतिहासिक संधि के रूप में उभरी। वार्साय की संधि के महत्व को इस तथ्य से चमकाया जा सकता है कि इसमें एक लीग वाचा निहित थी जिसने राष्ट्र संघ नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की थी।

तालिका–2

आधुनिक राज्यों की प्रणाली का कालक्रम

राज्य प्रणाली का वैश्विक विस्तार	
1600s	यूरोप (यूरोपियन सिस्टेम)
1700s +	नॉर्थ अमेरिका (वेस्टर्न सिस्टेम)
1800s +	साउथ अमेरिका, ओटोमान एम्पायर, जापान (ग्लोबलाइजिंग सिस्टेम)
1900s +	एशिया, अफ्रीका, कैरिब्बियन, पैसिफिक (ग्लोबल सिस्टेम)

स्रोतः जैक्सन और सोरेनसन[5]

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में सुपर शक्तियों का उदय देखा गया–संयुक्त राज्य अमेरिका और यू.एस.एस.आर. ने अपने अविश्वास के साथ एक विस्तारित शीत युद्ध की अवधि में दुनिया का नेतृत्व किया। 1989 में साम्यवाद की समाप्ति और यू.एस.एस.आर. के अंतिम पतन के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के अस्तित्व में आने के साथ ही एक–ध्रुवीयता का उदय हुआ। एक–ध्रुवीयता की इस अवधि में भूमंडलीकरण नामक दुनिया में एक नई ताकत का उदय हुआ। जैसे–जैसे राज्य वैश्वीकरण से प्रभावित होते गए, इक्कीसवीं सदी में कई विद्वान इस बात की वकालत करने लगे कि वैश्वीकृत दुनिया में राज्य की प्रासंगिकता बेमानी हो जाएगी। हालांकि, यह सच नहीं था, हालांकि, निस्संदेह, वैश्वीकरण ने राज्यों को प्रभावित करना जारी रखा है, इसने दुनिया में पूर्ण शक्ति के प्रदर्शनकारी[6] के रूप में राज्यों की प्रकृति को बदल दिया है। भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था में भी राज्य की भूमिका बरकरार है क्योंकि वैश्वीकरण केवल कानून के शासन और एक स्थिर सामाजिक व्यवस्था के साथ ही फल–फूल सकता है जो केवल राज्य कहे जाने वाले उपकरण द्वारा गारंटी दी जा सकती है।

3. स्टेट्स सिस्टेम: अस्तित्व के तीन प्रमुख कारक

3.1 राष्ट्रीय हित

अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संप्रभु संस्थाओं की आकांक्षाओं और लक्ष्यों का वर्णन करने के लिए राज्यों की स्थापना के बाद से राजनेताओं और विद्वानों द्वारा "राष्ट्रीय हित" शब्द का उपयोग किया गया है। राष्ट्रीय हित की धारणा राष्ट्रीय कल्पना और राजनीतिक बयानबाजी दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिज्ञों, इतिहासकारों, थिंक टैंकों, सरकारी सलाहकारों आदि द्वारा पूरे इतिहास में "राष्ट्रीय हित" के लिए बताई गई विभिन्न परिभाषाएँ अक्सर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति (ब्रांड्स)[1] में नाटकीय परिणाम देती हैं।[1] विदेशी विदेश मंत्री, सैन्य रणनीतिकार और शिक्षाविद महत्वपूर्ण हितों की चर्चा करते हैं। उनके देशों ने सुझाव दिया है कि हर कोई ठीक से समझता है कि उनका क्या मतलब है और शब्द के उपयोग से सही अनुमान लगाएगा। विदेश नीति विश्लेषण में, "राष्ट्रीय हित" की अवधारणा को अन्य चर की तुलना में काफी अधिक व्याख्यात्मक क्षमता प्रदान की गई है। यह ज्यादातर विदेश नीति में एक विश्लेषणात्मक उपकरण के रूप में किसी राज्य की विदेश नीति के उद्देश्यों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय हित हमेशा उन बुनियादी निर्धारकों का उपयोग करता है जो एक राज्य द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अन्य राज्यों के संबंध में राज्य की नीति का मार्गदर्शन करते हैं। चार्ल्स बीयर्ड, (सिंह[9] में उद्धृत) के अनुसार, यूरोप में सोलहवीं शताब्दी के दौरान "लेक्सस" ने राजनीतिक लाभ में गति प्राप्त की, जब इसने रासन डीश्एटैट (एक देश की विदेश नीति के लिए औचित्य) को इस आधार पर प्रतिस्थापित किया कि राष्ट्र का अपना हित राष्ट्रीयता के विचार के क्रमिक विकास के दौरान प्राथमिक हैं)। व्यक्त विचार पूरे समाज के हित का था। लेकिन काटजेंस्टीन[10] ने कहाः प्रणालीगत सिद्धांत अपर्याप्त है क्योंकि यह पर्याप्त रूप से सराहना नहीं करता है कि राज्यों का आंतरिक स्वरूप अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में उनके व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। उनके विश्लेषण में जोर घरेलू मानक संरचना पर है और यह राज्य की पहचान, हितों और नीतियों को कैसे प्रभावित करता है। राष्ट्रीय हितों की जड़ एक राष्ट्र की उत्तरजीविता और सुरक्षा बनी हुई है।

3.2 भूराजनीति

जोहान रुडोल्फ जेल्लेन एक स्वीडिश राजनीतिक वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने पहली बार वस जियो पॉलिटिक्स[3] (एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका)[3] शब्द गढ़ा था। वहीं एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका[3] भूराजनीति का वर्णन करती है– अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों में विद्युत सम्बंधों पर भौगोलिक प्रभावों का विश्लेषण। समकालीन प्रवचन में, भूराजनीति को व्यापक रूप से अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए एक ढीला पर्याय के रूप में नियोजित किया गया है। इसलिए, भूराजनीति विदेश नीति विश्लेषण का एक तरीका है जो राज्य के राजनीतिक व्यवहार को भू राजनीतिक चर के उपयोग के आधार पर समझाने की कोशिश करता है। नॉर्थ, वालिस और वेनगास्ट[7] का दावा हैः सभी समाज दुनिया भर में और उनके भीतर यादृच्छिक और अप्रत्याशित परिवर्तनों के अधीन हैं। बाहरी कारकों जैसे जलवायु और पड़ोसी समूहों के साथ–साथ आंतरिक कारकों में परिवर्तन जैसे नेताओं की पहचान और चरित्र, आंतरिक झगड़े और विवाद, ये सभी उन परिस्थितियों में लगातार परिवर्तन में योगदान करते हैं जिनके साथ समाज को सामना करना होगा। इसलिए, यह मानना उचित है कि भू–राजनीति एक गतिशील अवधारणा है।[4]

कई प्रमुख कारण हैं जो इस बदलाव को सत्ता में लाते हैं। किसी राष्ट्र की जनसांख्यिकी उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण है और जनसंख्या संरचना में परिवर्तन दोनों विकसित और विकासशील देशों के भीतर नाटकीय प्रभाव डाल सकते हैं। किसी देश की बहुसंख्यक आबादी की शैक्षिक प्राप्ति उस विशेष देश के भू–राजनीतिक प्रभाव को परिभाषित कर सकती है। एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था भी विश्व शक्ति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।[5,6,9] जी 7 देशों, अर्थात्, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान राज्यों के बीच हेग्मोनिक स्थिति है। इसके अलावा, सैन्य ताकत हमेशा राष्ट्रीय शक्ति के प्रमुख मापों में से एक है। सैन्य क्षमता

एक राज्य को अन्य राज्यों पर अपनी भूराजनीतिक शक्ति का शारीरिक अभ्यास करने का साधन प्रदान करती है। वर्तमान में, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस विश्व मंच पर दो सबसे शक्तिशाली सैन्य भू–राजनीतिक खिलाड़ी हैं। दुनिया में व्यावहारिक रूप से कोई संघर्ष नहीं है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों को शामिल नहीं करता है। हो सकता है कि कोई देश आज भौगोलिक रूप से उतना शक्तिशाली न हो, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है। दुनिया भर में, राष्ट्र से अधिक राष्ट्र से सत्ता की भौगोलिक परिवर्तन, और जनसंख्या, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, सैन्य और समाज जैसे दुनिया की गतिशीलता पर भारी संरचना का व्यापक प्रभाव पड़ता है। सबसे अधिक शक्ति वाला राष्ट्र दूसरों पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। एक बहु–ध्रुवीय भूमंडलीकृत दुनिया में, कोई भी देश उन सभी मापदंडों पर हावी नहीं हो सकता है जो विश्व राज्य प्रणाली का गठन करते हैं। किसी भी संदर्भ में भू राजनीतिक महत्व है कि तत्वों के आधार पर आधिपत्य छितराया हुआ है।

3.3 शक्ति संतुलन

पॉवर ऑफ बैलेंस (बी.ओ.पी.) की अवधारणा राज्यों के व्यवहार को समझाने में एक उपयोगी उपकरण हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों में एक अवधारणा के रूप में बी.ओ.पी. का इस्तेमाल सोलहवीं शताब्दी से बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में किया गया था, ताकि सत्ता प्रभुत्व[8] को रोकने के लिए नीति के एक उपकरण का वर्णन किया जा सके। 1815 से 1914 तक यूरोपीय राज्यों की प्रणाली हेगोमोनिक महत्वाकांक्षाओं की खोज पर अंकुश लगाने के लिए एक साधन के रूप में बी.ओ.पी. के उपयोग का एक उदाहरण था। इसके अतिरिक्त, पवन सिंह[9] बताते हैं: हेडली बुल ने कहा कि बी.ओ.पी. ने विजय के माध्यम से एक सार्वभौमिक साम्राज्य के गठन को रोका है। बुल के अनुसार, बी.ओ.पी. ने न केवल असतत राज्यों की स्वतंत्रता की रक्षा की है, बल्कि कूटनीति और अधिक से अधिक प्रबंधन जैसे संस्थानों के विकास को भी सुविधाजनक बनाया है। बी.ओ.पी. के अनुसार, हम जिस दुनिया में रहते हैं वह एक ऐसी प्रणाली है जहाँ देश एक पूर्ण संतुलन में मौजूद हैं।[10] बी.ओ.पी. सिद्धांत कहता है कि अगर प्रणाली में एक राज्य नाटकीय रूप से अपनी शक्ति बढ़ाता है तो प्रणाली का संतुलन गड़बड़ा सकता है। इस व्यवस्था में अन्य राज्यों को बाध्य करेगा कि वे एक राज्य के रूप में संतुलन बनाए रखें या एक राज्य द्वारा शक्ति में वृद्धि के कारण पहले स्थान पर गड़बड़ी की गई संतुलन को फिर से स्थापित करने के लिए अपनी शक्तियों को बढ़ाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात, बी.ओ.पी. से लिया गया एक शब्द है बैलेंस ऑफ टेरर। बैलेंस ऑफ टेरर में, एक राज्य का नेता विश्वसनीय रूप से दूसरे राज्य के नेता को विनाश की धमकी देता है।[11] शीत युद्ध के दौरान, अमेरिका और यू.एस.एस.आर. ने अक्सर परमाणु निरोध के लिए विशिष्ट संदर्भ में इस शब्द का उपयोग किया था।

4. निष्कर्ष

मानव राजनीतिक संगठनों के लंबे इतिहास में, राज्यों की प्रणाली ढीली, गतिहीन साम्राज्यों की तुलना में कम विकसित हुई है, परन्तु युद्ध, विजय और गुलामी राजनीतिक स्वतंत्रता के सबसे उल्लेखनीय सहसम्बंध थे। राज्यों के अधिकांश निकाय अंततः निरंतर युद्ध के माध्यम से ढह गए, पड़ोसी साम्राज्यों और राज्यों द्वारा कब्जा कर लिया गया। यूरोप और फिर दुनिया भर में आधुनिक राज्यों के उदय के बारे में एक कथा प्रबुद्धता की बौद्धिक खेती और उन विचारों को ठोस राजनीतिक संस्थानों में स्थानांतरित करने पर केंद्रित है, जो सदियों से चली आ रही प्रक्रिया है। प्रत्येक राज्य अनूठे तरीकों से विकसित होता है ताकि परिवर्तन की गहरी समझ व्यापक सामान्यीकरण से परे उस राज्य की राजनीतिक विरासत की एक विशिष्ट समझ से परे हो। दुनिया लगातार बदलती रहती है, और नए कार्यों और परिवर्तनों द्वारा राज्यों के कार्य को लगातार अप्रचलित किए जाने के बारे में हमारे विचार। जैसे–जैसे हम राजनीतिक रूप से संप्रभु राज्यों के एक युग के अंत में आते हैं, हम यह भी पहचानने लगे हैं कि राज्य की आत्मनिर्भरता हासिल करना कठिन है। हालांकि, यह पहचानना महत्वपूर्ण है, कि यद्यपि राज्य दुनिया में सबसे प्रमुख राजनीतिक इकाई बन गया है, फिर भी इराक में कुर्दों और आधुनिक इजरायल में फिलिस्तीन की तरह स्टेटलेस राष्ट्र हैं। लेकिन यह अनुत्तरित कई प्रश्नों को छोड़ देता है, और सबसे ऊपर, हम अभी भी आश्चर्यचकित हैं कि भविष्य में विभिन्न राज्य कैसे होंगे। निरंतर विकसित हो रही अपनी राज्य प्रणाली के साथ भूमंडलीकृत दुनिया किसी अन्य की तरह नहीं है जो कभी अस्तित्व में है। क्या हम छात्रों को खुद को समझने और उससे निपटने के लिए तैयार कर सकते हैं? हम बेहतर कर सकते हैं अगर हम स्वेच्छा से अपने विषय क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्वयं को एक शैक्षिक विषय के रूप में आई.आर. की निरंतर प्रासंगिकता को बनाए रखने वाले राज्य प्रणाली का लगातार अध्ययन करने के लिए तैयार हैं।

संदर्भ

1. ब्रांड्स, एच0 डब्ल्यू0 (1999) राष्ट्रहित का विचार, राजनयिक इतिहास, खण्ड–23, मु0पृ0 239–261।
2. डीकुन्हा, एन0 (2013) अंतर्राष्ट्रीय कानूनः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परिचयात्मक पाठ, जर्मनीः लैम्बर्ट अकादमिक प्रकाशन।

3. britannica-com/biography/RudolfKjellen#ref135068 (एक्सेस किया गया 11–08–2019) इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, (2019) रुडोल्फ केजेलनः स्वीडिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट। britannica-com/biography/RudolfKjellen#Ref135068- (अभिगमन 11–08–2019)।
4. हेवुड, ए0 (2013) राजनीति, 4 वां संस्करण, लंदनः पालग्रेव मैकमिलन।
5. जैक्सन, आर0 एवं एंडसोरेंसन, जी0 (2013) अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय सिद्धांत और दृष्टिकोण, 5 वां संस्करण, ऑक्सफोड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
6. मैकग्लिनी, एस0 (2017) अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ब्रिस्टल, इंग्लैंडः ई–अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रकाशन।
7. उत्तर, डी0 सी0; वालिस, जे0 जे0 एवं वेइन्गास्ट, बी0 आर0 (2009) हिंसा और सामाजिक आदेशः रिकॉर्ड किए गए मानव इतिहास की व्याख्या के लिए एक वैचारिक ढांचा, न्यूयॉर्क, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
8. श्वेलर, आर0 एल0 (2016) विश्व राजनीति में शक्ति का संतुलन, ऑक्सफोर्ड रिसर्च इन साइक्लोपीडियाः राजनीति, यूएसए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
9. सिंह, पी0 (2018) सिविल सेवा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध, चेन्नई, मैकग्राहिल एजुकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड।
10. काटजेंस्टीन, पी0 (1996) सांस्कृतिक मानदंड और राष्ट्रीय सुरक्षा, इथाका, एनवाई और लंदन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी प्रेस।
11. अहमद, वकार एवं डी.कुन्हा, नेविल (2019) भारत के उच्च शिक्षा प्रणाली की ज्ञान अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्तता और चुनौतियां, अनुसंधान विज्ञान शोध पत्रिका, खण्ड–7, अंक–1, मु0पृ0 156–159। DOI: 10.22445/avsp.v7i1.28